



NEERAJ®

M.P.S.E. - 13
ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति
(Australia's Foreign Policy)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.
& Various Central, State & Other Open Universities

By: Ved Prakash Sharma, M.A. (Pol. Science)



NEERAJ
PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति (Australia's Foreign Policy)

Question Paper—June-2023 (Solved)	1-2
Question Paper—December-2022 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved)	1-2
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved)	1-2
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1
Question Paper—December, 2017 (Solved)	1
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
1.	आस्ट्रेलिया की विदेश नीति के अध्ययन का महत्त्व (Importance of Studying Australia's Foreign Policy)	1
2.	आस्ट्रेलिया की विदेश नीति के अध्ययन के दृष्टिकोण (Approaches to the Study of Australia's Foreign Policy)	9
3.	आस्ट्रेलिया की विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व (Determinants of Australia's Foreign Policy)	14
4.	नीति-निर्माण प्रक्रिया (Policy-Making Processes)	23
5.	आस्ट्रेलिया की आर्थिक रूपरेखा : भूमण्डलीकरण के निहितार्थ (Economic Profile of Australia: Implications of Globalisation)	30

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
6.	व्यापार, निवेश और सेवाएँ (Trade, Investment and Services)	42
7.	संयुक्त राज्य अमेरिका (United States America)	50
8.	चीन (China)	56
9.	भारत (India)	68
10.	इंडोनेशिया (Indonesia)	76
11.	प्रशान्त द्वीप मंच और आसियान (Pacific Island's Forum and ASEAN)	83
12.	एपेक और हिन्द महासागर (APEC and Indian Ocean)	92
13.	आप्रवास और शरणार्थी (Immigration and Refugees)	100
14.	पर्यावरण (Environment)	112
15.	मानवाधिकार (Human Rights)	122
16.	परमाणु हथियार प्रसार (Nuclear Weapons Proliferation)	132



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति (Australia's Foreign Policy)

M.P.S.E.-13

समय : 2 घण्टे |

| अधिकतम अंक : 50

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग-I

प्रश्न 1. ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति से सम्बन्धित मध्य शक्ति के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-अध्याय-2, पृष्ठ-9, 'परिचय' तथा पृष्ठ-12, प्रश्न-3

प्रश्न 2. ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति निर्धारण में भू-आर्थिक तत्व किस प्रकार प्रमुख होते हैं, आकलन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-अध्याय-3, पृष्ठ-15, 'मूलनिर्धारक तत्व के रूप में भू-अर्थशास्त्र'

प्रश्न 3. ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति निर्माण में सामाजिक तत्वों की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-अध्याय-4, पृष्ठ-26, प्रश्न-1

प्रश्न 4. ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति पर भूमण्डलीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-अध्याय-5, पृष्ठ-37, प्रश्न-4

प्रश्न 5. शीतयुद्धोत्तर युग में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-अध्याय-6, पृष्ठ-46, प्रश्न-1

भाग-II

प्रश्न 6. विश्व स्तर पर अमेरिका के आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-अध्याय-7, पृष्ठ-54, प्रश्न-4

प्रश्न 7. चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभुत्व के सन्दर्भ में ऑस्ट्रेलिया व चीन के बदलते सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से दक्षिण चीन सागर (साउथ चाइना सी) पर चीन के अधिकार के दावों का विरोध किया है। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में अमरीका के साथ है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में एक घोषणा में ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि चीन के इन दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है।

ब्रूनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम जैसे देश चीन के इन दावों पर आपत्ति जताते हैं। इन देशों में इस इलाके को लेकर विवाद कई दशकों से जारी है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे लेकर तनाव बढ़ा है। इस दौरान समुद्र में कई बार टकराव भी हुए हैं। चीन 'नाइन-डैश लाइन' के नाम से मशहूर एक बड़े इलाके पर अपना दावा जाहिर करता है। चीन ने अपने दावों को पुख्ता आकार देने के लिए यहां टापू भी बना लिए हैं और समुद्र में गश्त करने लगा है।

चीन ने यहां एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। हालांकि, वह दावा यह करता है कि उसके मकसद शांतिपूर्ण हैं। आमतौर पर यहां रिहायश नहीं है, लेकिन इस इलाके में मौजूद दो आइलैंड चैन-पारासेल्स और स्प्रेटलिस के इर्द-गिर्द प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं। यह समुद्र एक प्रमुख शिपिंग मार्ग भी है। इसके अतिरिक्त चीन दक्षिण-चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं। मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए यह जल क्षेत्र महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है।

2016 में एक अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने चीन के खिलाफ फैसला दिया था। इस ट्राइब्यूनल ने कहा था कि इस बात के कोई

2 / NEERAJ : ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति (JUNE-2023)

प्रमाण नहीं हैं कि चीन का इस इलाके पर ऐतिहासिक रूप से कोई अधिकार रहा है, लेकिन चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर में चीन के लंबे वक्त की ऐतिहासिक गतिविधि के जरिए स्थापित हुए ऐतिहासिक दावे या समुद्री अधिकारों और हितों को खारिज करता है।

इसमें पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के 2016 के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है, “दक्षिण चीन सागर में चीन के मैरीटाइम फीचर्स के सबसे बाहरी बिंदुओं को जोड़ने वाली बेसलाइन बनाने या आइलैंड ग्रुप बनाने का कोई कानूनी आधार नहीं है।”

ऑस्ट्रेलिया चीन के इस बात पर जोर देने को स्वीकार नहीं करता है कि पारासेल्स और स्प्राटलिस पर उसकी संप्रभुता के दावे को बड़े स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मान्यता हासिल है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में वियतनाम और फिलीपींस की आपत्तियों का हवाला दिया है।

विश्लेषकों का कहना है कि यह वक्तव्य ऑस्ट्रेलिया की पहले की स्थिति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। पहले ऑस्ट्रेलिया

अपील करता था कि दक्षिण चीन सागर पर दावा करने वाले सभी देशों को इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सुलझाना चाहिए।

प्रश्न 8. शीतयुद्धोत्तर युग में ऑस्ट्रेलिया व आसियान के आर्थिक सम्बन्धों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-अध्याय-11, पृष्ठ-89, प्रश्न-4

प्रश्न 9. ऑस्ट्रेलिया की एपेक (एशिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग विकसित करने की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-अध्याय-12, पृष्ठ-92, 'परिचय', पृष्ठ-93, 'ऑस्ट्रेलिया और एपेक'

प्रश्न 10. पर्यावरण संरक्षण हेतु ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-अध्याय-14, पृष्ठ-118, प्रश्न-2, तथा प्रश्न-3



NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

आस्ट्रेलिया की विदेश नीति (Australia's Foreign Policy)

आस्ट्रेलिया की विदेश नीति के अध्ययन का महत्त्व (Importance of Studying Australia's Foreign Policy)



परिचय

हिन्द और प्रशान्त महासागरों पर आस्ट्रेलिया की भौगोलिक अवस्थिति को देखते हुए उसका एक अधोस्थित देश के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिसका विश्वस्तरीय विषयों में बहुत कम महत्त्व है। आस्ट्रेलिया अपनी भौगोलिक भौतिक अवस्थिति के कारण ही नहीं, अपितु अपनी अधोस्थित अवस्थिति (Geo-physical Profile) की वजह से अंतर्राष्ट्रीय विषयों में शामिल हुए बिना नहीं रह सकता। प्रमुख बात यह है कि आस्ट्रेलिया शक्ति केन्द्रों से दूर स्थित है। इन सभी कारणों के बावजूद आस्ट्रेलिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अलग-अलग समय पर शनैःशनैः शामिल होने की कोशिश करनी पड़ी है। आस्ट्रेलिया ने उत्तरी अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी ऐतिहासिक मित्रता के साथ ही एशिया के राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक मामलों में अत्यधिक दिलचस्पी दिखाई है। मात्र यही नहीं, हाल ही के वर्षों में आस्ट्रेलिया की जीवन्त अर्थव्यवस्था (Vibrant Economy) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह में गहराई से शामिल हो रही है।

इस अध्याय के अन्तर्गत एशिया-प्रशान्त के देशों के साथ आस्ट्रेलिया के आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी मामले, राजनीतिक और आर्थिक आजादी के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता सहित उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यतंत्र जैसे क्षेत्रों में भारत और आस्ट्रेलिया के मध्य उत्पन्न हुई समानताओं को उजागर करना,

शीत युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक स्वतंत्र विदेश नीति और रुख अपनाने के आस्ट्रेलिया के प्रयासों का विश्लेषण तथा एक सामूहिक लक्ष्य के प्रति आस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुसांस्कृतिक नीति और परस्पर सहायक प्रयासों की समीक्षा आदि की चर्चा की गई है।

अध्याय का विहंगावलोकन

आस्ट्रेलिया की घरेलू शक्तियाँ

विगत कुछ दशकों में आस्ट्रेलिया के राजनीतिक समूहों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके देश की सुरक्षा और समृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी राजनीतिक, रक्षा और गुप्तचर तंत्र संबंधी भागीदारी की मजबूती पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आस्ट्रेलिया के घोषित मूल्यों, सामाजिक-राजनीतिक संस्थाओं की अंतर्निहित शक्ति और विविधतापूर्ण विश्वस्तरीय संपर्क स्थापित करने के इसके साझा प्रयास ने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता और आर्थिक वैश्वीकरण के दौर में तीव्रता से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। यही कारण है कि इसके प्रमुख संबंधों का महत्त्व बढ़ रहा है। विदेश नीति संबंधी प्रयासों में भारत और आस्ट्रेलिया के मध्य कुछ मामलों में उल्लेखनीय समानताएँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आस्ट्रेलिया के नीतिगत प्रयास संसार में अन्य उदारवादी

2/NEERAJ : आस्ट्रेलिया की विदेश नीति

लोकतंत्रों के साथ काम करने की परंपरा बना लेने के कारण मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की ओर गतिशील हुए हैं।

भारत की भांति आस्ट्रेलिया ने कई वर्षों में जो संसदीय शासन प्रणाली विकसित की है, वह उसकी विदेश और व्यापार नीति के विचार-विमर्श के लिए एक विशाल मंच प्रदान करती है। एशियाई देशों के साथ आस्ट्रेलिया की सक्रिय भागीदारी को सरलता से देखा जा सकता है। आज आठ एशियाई देश आस्ट्रेलिया के दस सबसे बड़े निर्यात बाजार बन चुके हैं। भारत ने भी आस्ट्रेलिया के निर्यातों में छठा स्थान बना लिया है। आस्ट्रेलिया की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध तथा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंध-अंतर्राष्ट्रीय मामलों, इन दो क्षेत्रों को लाभकारी बनाए रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आस्ट्रेलिया का रक्षा और गुप्तचर संबंधी समझौता एशिया में उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। आस्ट्रेलिया पश्चिमी गठबंधन व्यवस्था के अवशेषों से मुक्त होकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करता रहा है।

क्रियात्मक बंधुत्व के माध्यम से गठबंधन निर्माण

क्रियात्मक बंधुत्व के संबंध में अत्यधिक विचार-विमर्श करने की जरूरत है। जहाँ एक ओर भौगोलिक-आर्थिक एकीकरण जारी रखने की संभावना है, जिसमें दूरस्थ कार्यरत छोटे गैर-राष्ट्रीय समूहों से सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है, ऐसी स्थिति में आस्ट्रेलिया का मानना है कि उसे अपने हितों को अत्यधिक बढ़ाना होगा। हाल के वर्षों में इन्हीं उद्देश्यों से आस्ट्रेलिया भीतर और बाहर समझौते स्थापित करने की कोशिश करता रहा है। आस्ट्रेलिया गुप्त सूचनाओं के संग्रह और भागीदारी के क्षेत्र में उस साझेदारी को जारी रखता है जो उसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ स्थापित की थी। आस्ट्रेलिया गैट (GATT) और एपेक जैसे विश्वस्तरीय मंचों में बहुपक्षीय मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने में अत्यधिक सक्रिय रहा है। कृषि व्यापार के कैन्स समूह ने सौदेबाजी के उद्देश्य से आस्ट्रेलिया के नेतृत्व में कृषि व्यापार में सुधार की मांग की और उसमें सफलता भी हासिल की है। यह पहल आस्ट्रेलिया की एक रचनात्मक और प्रभावी बहुपक्षीय कूटनीति का संकेत है, जिसने सदस्यों के कठिन प्रक्रिया हेतु एकत्रि कर दिया।

बहुपक्षीयता से द्विपक्षीयता की ओर

आस्ट्रेलिया राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करने के लिए संसारभर में अपने द्विपक्षीय संबंधों की ताकत पर निर्भर करता है। आस्ट्रेलिया की व्यापार और विदेश नीति के दैनिक कार्यों एक अत्यधिक भाग

द्विपक्षीय पक्ष-समर्थन में विद्यमान है। बुनियादी तौर पर द्विपक्षीय पक्ष-समर्थन और सहयोग विश्वस्तरीय और क्षेत्रीय पहलुओं का समाधान करने के लिए आवश्यक है। आस्ट्रेलिया का प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे कानूनों को कठोरता से अपनाएं करें और आतंकी समूहों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए क्षमताओं को विकसित करें। आस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय नीतियाँ एक सामूहिक उद्देश्य के लिए एक-दूसरे के लिए सहयोगी हैं। संयुक्त राष्ट्र में आस्ट्रेलिया दूसरी सभी देशों की तरह सही सिद्धांतों पर काम करता है और उन पहलुओं को उजागर करता है, जो उसके हित में होते हैं।

आस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्पर्क

आस्ट्रेलिया की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की सशक्तता और घरेलू ताकत ने आस्ट्रेलिया को इतनी मजबूती प्रदान की है कि वह अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की समस्याओं का उचित तरीके से मुकाबला कर सकता है। आस्ट्रेलिया की आशाएँ सदैव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संपर्कों पर आश्रित रही हैं। इसका घरेलू औद्योगीकरण ज्यादातर विदेशी निवेश और उससे होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण संभव हुआ है। विगत दो दशकों में आर्थिक सुधार के फलस्वरूप आस्ट्रेलिया के व्यापार और निवेश संपर्क और ज्यादा गहरे हुए हैं। 1990 के दशकों के दौरान विकसित अर्थव्यवस्था में आस्ट्रेलिया में उत्पादकता की वृद्धि फिनलैंड के बाद उच्च स्तर पर थी। आस्ट्रेलिया के पूंजी बाजार को निजीकरण और निगमित शासन और कर सुधारों ने और ज्यादा व्यापक बनाने में सहायता की तथा साझा स्वामित्व को सुगम किया है। इन सुधारों ने आस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। इन सुधारों की वजह से आस्ट्रेलिया का संसार में शेयर और इक्विटी बाजारों में 9वां स्थान हो गया है। इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आस्ट्रेलिया के पूंजी बाजारों में अत्यधिक मात्रा में अपना धन निवेश कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया के सुरक्षा सम्पर्क

आस्ट्रेलिया की मजबूत सुरक्षा ताकतों ने इस क्षेत्र के अंदर और बाहर स्थित देशों से निपटने के प्रति इसके आत्मविश्वास को बल प्रदान किया है। आतंकवाद के मुद्दे पर एशियाई देशों के साथ आस्ट्रेलिया के अन्य रक्षा तथा कानून प्रवर्तन संबंधी रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आई है। हाल ही के वर्षों में आस्ट्रेलिया ने इन संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। इन प्रयासों से आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और जनसंहार के

हथियारों के प्रसार जैसे प्रमुख पहलुओं पर सहयोग करना और ज्यादा सहज हो जाता है।

आस्ट्रेलिया-भारत अभिसरण

आस्ट्रेलिया और भारत के मध्य भू-राजनीतिक अभिसरण (Convergence) का विकास दिखाई देता है। इन दोनों देशों के मध्य केवल सामरिक सुरक्षा हितों की परस्पर मान्यता ही निहित नहीं है, अपितु द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबद्ध होने की रुचि भी विद्यमान है। दोनों देशों के व्यापार संबंध भी अत्यंत मजबूत हैं। वर्तमान में संसार का आधा समुद्री व्यापार मलक्का और लोम्बोक जलडमरू-मध्य के द्वारा ही होता है, जिसमें आस्ट्रेलिया और भारत का व्यापार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 1990 में भारत ने आर्थिक उदारवाद की नीति को अपनाया। 1990 के दशक से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों का दौर शुरू हो गया। हाल ही के वर्षों में आस्ट्रेलिया से खनन उपकरण तथा विद्युत यंत्रों सहित व्यापक तरीके से निर्मित विनिर्माण के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। भारत से आस्ट्रेलिया में होने वाले आयातों में मोती और रत्न तथा वस्त्र आदि सम्मिलित हैं। अधिकांशतः कैनबरा में अब यह माना जाने लगा है कि आस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति के लिए भारत के आर्थिक उत्थान प्रमुख सहायक होंगे।

आतंकवाद के मुद्दे पर आस्ट्रेलिया ने भारत के इस दावे पर कभी भी विश्वास नहीं किया था कि 'सीमापार' आतंकवाद उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वास्तविक रूप से खतरा है। लेकिन बाली पर हुए आतंकवादी हमलों ने आस्ट्रेलिया को अपना रवैया बदलने के लिए विवश कर दिया। इसी बीच 2003 में आस्ट्रेलिया ने दूसरे देशों की भांति भारत के साथ भी आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी और गुप्त सूचनाओं की भागीदारी के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन पत्र में दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग और निगरानी के लिए रक्षा संबंधी भारत-आस्ट्रेलिया सामूहिक कार्य समूह की स्थापना का भी प्रावधान है।

अभ्यास-प्रश्न

प्रश्न 1. आस्ट्रेलिया की घरेलू शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-ऑस्ट्रेलिया अपनी सीमित सैन्य शक्ति के कारण विश्वव्यापी स्तर पर बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पायेगा। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा नीतियों के प्रमुख तत्त्वों में सैन्य क्षमता, कूटनीति, आर्थिक सम्बन्ध, सहयोग, सैन्य खतरों का सामना करने की क्षमता तथा विचारों के आदान-प्रदान जैसे तत्त्वों को शामिल किया गया है। आस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय सुरक्षा नीतियों को

ध्यान में रखते हुए वचनबद्धता पर विशेष जोर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। भौगोलिक रूप से आस्ट्रेलिया को एशिया तथा मनोवैज्ञानिक रूप से यूरोप का भाग माना जाता है। इसी स्थिति के कारण आस्ट्रेलिया दक्षिण-पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। आस्ट्रेलिया अब दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी पर जोर दे रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र आस्ट्रेलिया के रक्षा विशेषज्ञों के लिए महत्त्वपूर्ण हो गया है।

संसारभर में अन्य उदारवादी लोकतंत्रों के साथ काम करने की परंपरा बना लेने के कारण आस्ट्रेलिया के नीतिगत प्रयास ऐसे मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की ओर प्रवृत्त हैं। हाल ही के दशकों में आस्ट्रेलिया की विदेश नीति में एशिया के देशों के साथ और भी ज्यादा घनिष्ठ संबंधों को वरीयता प्रदान की गई है। वर्तमान में आठ एशियाई देश आस्ट्रेलिया के दस सबसे बड़े निर्यात बाजार बन चुके हैं।

आस्ट्रेलिया पश्चिमी गठबंधन प्रणाली के अवशेषों से स्वतंत्र होकर संसार के मामलों में एक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध-अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे क्षेत्रों में मृदु संबंध बनाए रखना ही आस्ट्रेलिया की विदेश नीति का स्पष्ट लक्षण है। वर्तमान में आस्ट्रेलिया की सशक्तता को देखते हुए उत्तरी गोलार्ध की अनेकानेक कम्पनियों ने आस्ट्रेलिया में अपने एशियाई मुख्यालय स्थापित किए हैं और इसका प्रमुख कारण एशिया के साथ आस्ट्रेलिया की घनिष्ठता तथा उसके एशियाई कौशलों की गहनता और निवेश का वातावरण निर्माण करना। आने वाले वर्षों में आस्ट्रेलिया का एशिया के साथ गहरा संबंध बना रहेगा। साथ ही आस्ट्रेलिया उन सुरक्षा संबंधी और आर्थिक हितों पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करेगा, जो उसके वर्तमान एशियाई संबंधों को मजबूत करते हैं।

प्रश्न 2. हाल के वर्षों में एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में आस्ट्रेलिया की स्थिति का आकलन कीजिए।

उत्तर-आस्ट्रेलिया 'एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग संगठन' एपेक का प्रमुख घटक रहा है। एपेक के एजेंडे में व्यापार और निवेश, उदारीकरण, आर्थिक सहयोग तथा विभिन्न देशों को परामर्श देने की नीति शामिल है। एपेक एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करने के लिए सूचना तंत्र प्रदान करता है। एपेक की प्रथम बैठक 1989 में ऑस्ट्रेलियाई राजधानी कैनबरा में हुई थी। उस समय से लेकर अब तक एपेक एक महत्त्वपूर्ण संगठन बन चुका है। विश्व के सकल घरेलू

4/NEERAJ : आस्ट्रेलिया की विदेश नीति

उत्पादन का आधा हिस्सा एपेक देशों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके 21 सदस्य हैं, जिनमें उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया तथा ओशनिया प्रमुख हैं। ऑस्ट्रेलिया एपेक का एक महत्वपूर्ण सदस्य है तथा 2020 तक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों तथा निवेशकों के लिए क्षेत्रीय बाजार विकास सुधार महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया एपेक के अन्य देशों को दो तिहाई व्यापारिक तथा सेवाओं का निर्यात करता है। आस्ट्रेलिया के प्रयास एपेक तक सीमित नहीं हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार दक्षिणी अमेरिकी देशों के साथ भी सम्बन्ध मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। ऑस्ट्रेलिया भारतीय महासागर में भी आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान दे रहा है।

अगले कुछ वर्ष बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए मुश्किल होंगे। ऑस्ट्रेलिया सहस्रत्राब्दी राउंड का समर्थन करता है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे आस्ट्रेलियाई निर्यातकों को लाभ होगा। उसने 1990 तथा 2000 में कृषि तथा सेवा समझौतों के लिए प्राथमिकताएँ सुनिश्चित की हैं। आस्ट्रेलिया उदारीकरण से व्यापक लाभ प्राप्त करने में समर्थ रहा है। सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि व्यापार समझौते पर उरूग्वे बैग के बाद से सभी प्रावधान लागू होने पर आस्ट्रेलियाई आय में 5 अरब डॉलर प्रतिवर्ष की वृद्धि का अनुमान है, जिसके कारण आस्ट्रेलियाई लोगों के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे। आस्ट्रेलिया ने विश्व कृषि समझौतों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आस्ट्रेलिया अन्य समझौतों के माध्यम से भी अपने हितों को बढ़ा सकता है; जैसे सीमा शुल्क में हुई कमी से आस्ट्रेलिया के दूर संचार निर्यात में लगभग 4000 लाख डॉलर की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय सेवाओं पर विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में आस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण भागीदार है। आगे आस्ट्रेलियाई निर्यातकों तथा निवेशकों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे आस्ट्रेलिया में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

1986 में इसकी स्थापना हुई, जिसके 14 सदस्य थे। इस समूह के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया ने कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों को पूरा किया। इसके 14 देशों (अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलम्बिया, फिजी, हंगरी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैण्ड, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड तथा उरूग्वे) ने लघु कृषि व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व किया। आस्ट्रेलिया कृषि में मुक्त व्यापार का पक्षधर था। आस्ट्रेलिया ने संरक्षणवाद को कम करने तथा कृषि में आर्थिक सहायता को कम करने का प्रयास किया।

प्रश्न 3. 1990 के दशक से आस्ट्रेलिया और भारत के घटनाएँ आपसी आर्थिक और सुरक्षा संबंधों की विवेचना कीजिए।

उत्तर—1990 के दशक के दौरान आस्ट्रेलिया में उत्पादकता की वृद्धि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में फिनलैंड के बाद सबसे ज्यादा थी। अन्य देशों की तरह आस्ट्रेलिया का भारत के साथ भी सम्बन्ध बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भारत-ऑस्ट्रेलिया के सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं थे तथा दोनों के बीच कई बातों पर मतभेद भी था, परन्तु वर्तमान में दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध हैं तथा ऑस्ट्रेलिया भारत को अन्य देशों के समान ही महत्व दे रहा है। 1980 के दशक के मध्य से ऑस्ट्रेलिया को लगने लगा कि उसके लिए भारत की उपेक्षा करना हितकारी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य हर प्रकार के सहयोग को बढ़ाने के लिए विकास मंचों की स्थापना की गई। इन मंचों में कई प्रकार की समितियाँ तथा विभाग शामिल थे; जैसे—भारत संयुक्त व्यापार परिषद् संयुक्त व्यापार समिति, संयुक्त कोयला समिति, तथा उच्च स्तरीय सलाहकार इत्यादि। भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच विस्तृत विकास सहयोग कार्यक्रम है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का खुला रूप भी ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलियाई उत्पादकों तथा निर्यातकों को भारत के बाजारों से लाभ प्राप्त हो सकेगा। ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि सन 2000 तक भारत आस्ट्रेलिया के सबसे बड़े 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक होगा।

आस्ट्रेलिया की मजबूत सुरक्षा शक्तियों ने इस क्षेत्र के भीतर और बाहर स्थित देशों से मुकाबला करने के लिए इसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। देश की तकनीकीय स्तर पर उन्नत सशस्त्र सेनाओं ने आस्ट्रेलिया को एशिया तथा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र की एक प्रमुख और सैन्य शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके निर्णायक और प्रभावी नेतृत्व ने आतंकवाद-विरोधी लड़ाई में उसके योगदान ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को ही नहीं, अपितु क्षेत्रीय सहयोग को भी आकर्षित किया है। बाली में हुए आतंकवादी हमलों की संयुक्त जांच में आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच घनिष्ठ संबंध ने इस प्रकार के संबंधों के महत्व को और सशक्तता प्रदान की है। इस प्रकार के प्रयासों से सुरक्षा मुद्दों पर विशेष रूप से आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और जनसंहारक अस्त्रों के प्रसार पर सहयोग करना आसान हो जाता है।